

## कोविड-19 महामारी का शिक्षा पर प्रभाव

### Impact of The Covid-19 Pandemic on Education

Paper Submission: 03/08/2021, Date of Acceptance: 20/08/2021, Date of Publication: 23/08/2021

आज सम्पूर्ण विश्व कोविड-19 महामारी से पीड़ित है। मानव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। जीवन के सभी क्षेत्रों में इसके प्रभाव परिलक्षित हो रहे हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो इस महामारी से प्रभावित न हुआ हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विश्व की सारी प्रगति, सारे विकास रुक से गये हैं। शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रह गया है। भारतीय शिक्षा प्रणाली पहले से ही खराब अवसंरचना व सुविधाओं आदि समस्याओं से जूझ रही है, कोविड-19 ने इसे और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया है। लॉकडाउन से कारण बन्द हुए विद्यालयों से शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गयी। इसने विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला। शिक्षण संस्थानों के बन्द होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई रुक गई, रोजगार का संकट आ गया वहीं दूसरी ओर इससे निपटने के प्रयास में हम ऑनलाइन शिक्षण की ओर उन्मुख हुए। इसने शिक्षण संस्थानों, शिक्षकों व विद्यार्थियों को ऐसी तकनीकों से जोड़ा जिनका पहले प्रयोग नहीं किया गया था। कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयों के बाद धीरे-धीरे हमने इस शिक्षण पद्धति को अपनाना प्रारम्भ कर दिया। इसके माध्यम से नई तकनीकों से जुड़कर हमने डिजिटल युग में प्रवेश किया। प्रस्तुत शोधपत्र में कोविड-19 के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों तथा कोविड-19 के शिक्षा व्यवस्था पर सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण किया गया है।

#### रश्मि सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर,

समाजशास्त्र विभाग,

महिला महाविद्यालय,

कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

Today the whole world is suffering from the COVID-19 pandemic. Man is fighting for his existence. Its effects are being reflected in all walks of life. There is no social, cultural, economic, educational, religious sector that has not been affected by this epidemic. It seems that all progress, all development of the world has come to a standstill. The field of education has also remained no exception to this. The Indian education system is already grappling with the problems of poor infrastructure and facilities, COVID-19 has made it even more challenging. The education system completely collapsed due to the schools being closed due to the lockdown. It also adversely affected the physical and mental health of the students. Due to the closure of educational institutions, the education of the students came to a halt, there was a crisis of employment, on the other hand, in an effort to deal with it, we turned towards online education. It connected educational institutions, teachers and students with technologies that had not been used before. After some initial difficulties, gradually we started adopting this teaching method. Through this, we entered the digital age by connecting with new technologies. In the present paper, the efforts of the government in the field of education during Kovid-19 and the positive and negative effects of Kovid-19 on the education system have been analyzed.

**मुख्य शब्द:** कोविड-19, शिक्षण पद्धति, अवसंरचना।

COVID-19, Teaching Method, Infrastructure.

#### प्रस्तावना

शिक्षा अपने मूल में समाजीकरण की एक प्रक्रिया है। जब-जब समाज का स्वरूप बदला है, शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ है। भारत सहित पूरे विश्व में कोविड-19 नामक ऐसी महामारी सामने आई जिसने हमारे समाज की मूलभूत संरचना को प्रभावित किया। सर्वप्रथम 31 दिसम्बर 2019 को चीन के वुहान में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया। इन परिस्थितियों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सबसे पहले सामाजिक दूरी का पालन करने की सलाह दी। भारत में 30 जनवरी 2020 को केरल में कोविड-19 का पहला मामला सामने आया। सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए भारत में 24 मार्च 2020 से लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। सभी विद्यालय, कालेज व उच्च शिक्षण संस्थान बन्द कर दिये गये। कक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं आदि अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गईं।

शिक्षा के इतिहास में प्रथम बार ऐसा हुआ कि किसी महामारी ने हमारी पारम्परिक शिक्षण पद्धति को अचानक से परिवर्तित कर हमें डिजिटल शिक्षा की ओर प्रेरित किया। कोरोना संकट के समय हमारे शिक्षण संस्थानों के समक्ष जो चुनौतियाँ आई हैं उसमें ऑनलाइन शिक्षण एक स्वाभाविक विकल्प दिखाई पड़ता है। यद्यपि यह इस महामारी की तात्कालिक समस्या से उपजी परिस्थिति है परन्तु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भविष्य में ऑनलाइन शिक्षा मात्र एक तकनीकी नहीं अपितु समाजीकरण की प्रक्रिया बन जाएगी।

परम्परागत भारतीय समाज में शिक्षा की तीन कड़ियाँ रही हैं- विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक। कोविड-19 ने इसमें एक कड़ी और जोड़ दी है वह है स्मार्टफोन/लैपटॉप/कम्प्यूटर। इस महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण ही सही डिजिटल शिक्षा के यथार्थ से हमारा परिचय सामूहिक रूप से हो रहा है। किसी भी कल्याणकारी सरकार के लिए शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत में दूरस्थ शिक्षा और डिजिटल शिक्षा के कार्यक्रमों की गति बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। हमारा देश वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है जिसमें शैक्षिक प्रौद्योगिकी, डिजिटल कार्यक्रम व वर्चुअल कक्षाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। डिजिटल शिक्षा को ऐसी शिक्षा माना जाता है जिसमें तकनीकी का प्रभावी प्रयोग करने वाली निर्देश प्रणाली शामिल हो। इसमें मिश्रित और वर्चुअल लर्निंग समेत कई प्रकार की पद्धतियाँ सम्मिलित होती हैं। ऑनलाइन शिक्षा का अर्थ ऑनलाइन उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग कर अध्ययन करना है। यह मोबाइल/कम्प्यूटर/टेबलेट आदि उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक सामग्री से जुड़ा होता है। मिश्रित शिक्षण पद्धति में वर्चुअल शिक्षा और पारम्परिक शिक्षण पद्धति दोनों का ही सम्मिश्रण होता है। दूरस्थ शिक्षा दूर से ही अध्ययन करने की प्रक्रिया है। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी भौतिक रूप से एक दूसरे से दूर होते हैं। कोविड-19 महामारी से शिक्षा को प्रभावित होने से बचाने के लिए उपर्युक्त सभी माध्यमों का प्रयोग किया गया।

भारत में लॉकडाउन के प्रारम्भ से अधिकांश शिक्षण संस्थाएँ शैक्षणिक कार्यों के लिए ऑनलाइन शिक्षा या ई-लर्निंग को एक विकल्प के रूप में प्रयोग कर रही हैं। पहले तो शिक्षक, छात्र और अभिभावक तीनों ही असमंजस में थे कि इस वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों में नई शिक्षण पद्धति के साथ सामंजस्य कैसे बिठाया जाय परन्तु धीरे-धीरे हमने इस परिवर्तन को स्वीकार लिया। देखते ही देखते घर क्वारंटीन ही नहीं अपितु ऑनलाइन कार्यों और ऑनलाइन शिक्षण के केन्द्र बन गये। बड़े पैमाने पर ऑनलाइन कोचिंग संस्थानों, डिजिटल कक्षाओं और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रतिस्पर्धा होने लगी। कक्षा में आमने-सामने के संप्रेषण का स्थान इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप आदि पर अभासी कक्षाएँ लेने लगी। शिक्षकों द्वारा अब ऑनलाइन व्याख्यान दिये जाने लगे। जूम गूगलमीट, गूगल क्लासरूप, फेसबुक, यूट्यूब आदि ऐप के माध्यम से शिक्षण सम्बन्धी गतिविधियाँ संचालित होने लगी। अभिभावकों, शिक्षकों विद्यार्थियों आदि को आपस में जोड़ने और बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए व्हाट्सऐप ग्रुप बनाए जाने लगे। शिक्षण सामग्री के उत्पादन और उपभोग का एक नया ई-मार्केट खुल गया क्योंकि ई-लर्निंग के तहत वर्चुअल कक्षाओं और वीडियो-ऑडियो सामग्री, प्रस्तुतियाँ, पाठ्यक्रम, वेबिनार, मॉक टेस्ट, आदि गतिविधियाँ भी ऑनलाइन संचालित हो रही हैं। डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में कोरसेरा, बाईजूस, वेदांतु और माइंडस्पार्क, जैसे ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म लगातार विस्तारित हो रहे हैं। 'भारत में ऑनलाइन शिक्षा 2021' की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 से 2021 के दौरान भारत में ऑनलाइन शिक्षा के कारोबार में आठ गुना की अभूतपूर्व वृद्धि आंकी गई है। यह 2016 में लगभग 25 करोड़ डॉलर का था जो 2021 में बढ़कर लगभग 2 अरब डॉलर होने की सम्भावना है। चूंकि डिजिटल लर्निंग को नवोन्मेषी, समय, संसाधन और दूरी की बचत वाला माध्यम माना जाता है इसलिए यूजीसी ने सुझाव दिया है कि अगले सत्र से कम से कम 25 प्रतिशत पाठ्यक्रम प्रत्येक शिक्षण संस्थान में ऑनलाइन पढ़ाया जाय। इसके लिए सभी शिक्षण संस्थान पर्याप्त आईसीटी ढाँचा विकसित कर अपने शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कराएँ और ई-लर्निंग सामग्री भी तैयार कराएँ। यदि इस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से कार्य हो तो डिजिटल शिक्षा का भविष्य अनेक सम्भावनाओं से भरा हुआ है।

**साहित्यवलोकन**

किसी भी शोध समस्या के अध्ययन में सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 'शेद्री, निखिल (मई 2020) ने अपने शोधपत्र "कोविड-19 के बाद भारत का भविष्य शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन" से प्राप्त निष्कर्षों में पाया कि इस महामारी के कारण विद्यार्थियों के शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। 46 प्रतिशत विद्यार्थियों ने अपने देश से बाहर अध्ययन का विचार त्याग दिया है। मात्र 13 प्रतिशत विद्यार्थी ही अध्ययन हेतु विदेश जाना चाहते हैं। वही एक दुखद पहलू यह भी है कि 8 प्रतिशत विद्यार्थी अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं। 57.1 प्रतिशत शिक्षाविद् मानते हैं कि कोविड के कारण शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन न तो बहुत अच्छे साबित होंगे और न ही बहुत बुरे। 19 प्रतिशत शिक्षाविदों का मानना है कि इसका शिक्षा पर प्रभाव बहुत नकारात्मक होने वाला है। शेष इसके बारे में अभी अनिश्चितता की स्थिति में हैं।

<sup>5</sup>धवन, शिवांगी (जून 2020) ने अपने शोधपत्र "ऑनलाइन लर्निंग:ए पैनैशिया इन द टाइम ऑफ कोविड-19 क्राइसिस" से प्राप्त निष्कर्षों में पाया कि ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से समय और स्थान सम्बन्धी लचीलापन आया है। एक साथ एक बड़ी कक्षा या कई कक्षाओं में शिक्षण किया जा सकता है। इसके माध्यम से नवाचार की नई सम्भावनाएं उत्पन्न हुई हैं साथ ही ऑनलाइन शिक्षण में त्वरित फीडबैक भी प्राप्त हो जाता है। परन्तु इसमें शिक्षण और विद्यार्थी के बीच प्रत्यक्ष वार्तालाप और भौतिक सम्पर्क समाप्त हो गया है। सभी शिक्षक और शिक्षार्थी ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण में सहज नहीं हो पाते जिससे कभी-कभी तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है।

<sup>6</sup>राज, उत्सव (जुलाई 2020) ने अपने शोधपत्र "इण्डियन एजुकेशन सिस्टम इन फाइट अगेन्स्ट कोविड-19 पैन्डमिक" में ऑनलाइन शिक्षण की समस्याओं का अध्ययन किया और पाया कि वर्ष 2017-18 में भारत में केवल 24 प्रतिशत शहरी परिवारों में इंटरनेट की सुविधा थी। 15 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या इंटरनेट का प्रयोग करती थी। वर्ष 2019 तक 77 प्रतिशत भारतीयों के पास स्मार्टफोन थे। 11 प्रतिशत भारतीय कम्प्यूटर/लैपटॉप/टैबलेट का प्रयोग करते थे। 50 प्रतिशत से भी कम लोग 12 घण्टे या इससे अधिक बिजली का प्रयोग कर पाते थे। इस स्थिति में भारत अभी ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था अपनाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं हैं।

**अध्ययन का उद्देश्य**

1. कोविड-19 के दौरान सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किये गये प्रयासों का अध्ययन।
2. कोविड-19 के शिक्षा पर सकारात्मक प्रभावों का अध्ययन।
3. कोविड-19 के शिक्षा पर नकारात्मक प्रभावों का अध्ययन।

**शोधपद्धति**

प्रस्तुत शोधपत्र में अध्ययन हेतु द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है जिसके अन्तर्गत विभिन्न राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों की रिपोर्ट, विश्वसनीय वेबसाइटों से प्राप्त रिपोर्ट, विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं व कोविड-19 से सम्बन्धित शोधपत्रों को सम्मिलित किया गया है।

**कोविड-19 के दौरान सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किये गये प्रयास**

मार्च 2020 से जब देशभर में लॉकडाउन लागू किया गया तो उसके तुरन्त बाद केन्द्र व राज्य सरकारों ने शिक्षा को ऑनलाइन करने का प्रयास प्रारम्भ कर दिया। इसके माध्यम से सामाजिक दूरी का पालन करते हुए शिक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने की बात की गई। इसके लिए टीवी, डीटीएच चैनल, रेडियो प्रसारण, व्हाट्सएप समूह, पिंट्री मीडिया व कई प्रकार के मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाने लगा। केन्द्र सरकार ने डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम को बढ़ावा दिया। यदि इस महामारी से इतर भी देखा जाय तब भी भारत जैसे देश में ऑनलाइन शिक्षा की अत्याधिक आवश्यकता है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप हमारे पास पर्याप्त विद्यालय, कॉलेज, शिक्षक व अन्य संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए समय और परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार ने डिजिटल शिक्षा व वर्चुअल लर्निंग के माध्यम से शिक्षा के प्रत्येक सतर (प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा) पर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। इस दिशा में भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं-

**दीक्षा (Digital Infrastructure for knowledge sharing).**

5 सितम्बर 2017 को शिक्षकों को डिजिटल मंच प्रदान करने और उन्हें प्रशिक्षण देने तथा शिक्षक समुदाय को एक साथ एक मंच पर लाने का अवसर देने के लिए सरकार द्वारा दीक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई। इस पोर्टल पर शिक्षकों को ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों तरीकों से प्रशिक्षण प्राप्त होगा। इस

पहल का दायरा बढ़ाते हुए इसमें शिक्षकों के लिए ई-सामग्री की उपलब्धता को बढ़ाने तथा गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास शामिल किया गया है। यह पोर्टल कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए है। इसके माध्यम से शिक्षक गुणवत्ता वाली सामग्री ले सकते हैं और उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा भी सकते हैं। यह मोबाइल कम्प्यूटर, टैबलेट आदि के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है। यह नियमित स्कूल पाठ्यक्रम के बाद, एन सी ई आर टी पाठ्यपुस्तकों और पाठों तक लाइसेंसिंग व्यवस्था है। यह भौतिक और डिजिटल दुनिया के बीच पुलका कार्य करता है।

### **<sup>8</sup>निष्ठा (National Initiative for School Head's and Teacher's Holistic Advancement)**

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय ने देशभर के लाखों शिक्षकों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए “निष्ठा योजना-2020” प्रारम्भ की। यह कार्यक्रम एनसीईआरटी ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का प्रयोग करके दीक्षा पर 42 लाख शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यह अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जिसमें सभी राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किये गये हैं। कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश सहित लगभग 15 राज्यों तथा सीबीएसई ने दीक्षा पर ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करने की तैयारी की थी। जून 2020 तक लगभग 60 लाख शिक्षकों ने इन पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण कराया। इनमें से 43 लाख शिक्षकों ने पाठ्यक्रम पूरे कर लिये। भारत सरकार ने कोविड-19 से जुड़े प्रशिक्षणों के लिए भी दीक्षा ऐप का प्रयोग किया।

### **<sup>9</sup>स्वयंप्रभा डीटीएच शैक्षिक चैनल**

- स्वयंप्रभा चैनल 24x7 आधार पर देश में सभी जगह 32 चैनलों के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करता है। यह चैनल उन लोगों तक आसानी से पहुंचते हैं जिनके पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसमें पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यसामग्री होती है जो विविध विषयों को सम्मिलित करती है।

### **<sup>10</sup>स्वयं (Study webs of Active- learning for young Aspiring Minds)**

यह एक एकीकृत मंच है जो स्कूल (9वीं-12वीं कक्षा) से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। स्वयं एनसीईआरटी कक्षा IX-XII तक के लिए 12 विषयों में विद्यालयी शिक्षा प्रणाली हेतु बड़े पैमाने पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का मॉड्यूल (Moocs) विकसित कर रहा है। ये 12 विषय व्यावसायिक अध्ययन, अकाउंटेंसी, जीवविज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, गणित, भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र हैं। ये 12 पाठ्यक्रम प्रथम चरण में प्रारम्भ किये गये थे इसके दूसरे चरण में 20 पाठ्यक्रमप्रारम्भ किये गये हैं

### **<sup>11</sup>एनआरओईआर (National Repository of open Educational Resources)**

यह मुक्त शैक्षिक सामग्री साझा करने वाला मंच है। इसे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रारम्भ किया था तथा इसे एनसीईआरटी का केन्द्रीय शिक्षा तकनीकी संस्थान संभालता है। इसपर एनसी ईआरटी की सभी पुस्तकें तथा प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए अनेक विषयों की शैक्षिक सामग्री विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। ये सामग्री विभिन्न फाइलों संग्रह, दस्तावेजों, ऑडियो, चित्रों व वीडियो के रूप में उपलब्ध है। यह प्लेटफार्म ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त लाभदायक है।

### **<sup>12</sup>राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (National Digital Library)**

यह एक ‘एकल- खिड़की खोज सुविधा’(Single-window search Facility) के तहत सीखने के संसाधनों के आभासी भंडार का एक ढांचा विकसित करने की परियोजना है। इसके माध्यम से यहाँ 3 करोड़ से अधिक डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं। इसमें लगभग 20 लाख सक्रिय उपयोगकर्ताओं के साथ 50 लाख से अधिक छात्रों ने अपना पंजीकरण कराया है। यह (NDL) एक मोबाइल एप के माध्यम से भी उपलब्ध है।

### **<sup>13</sup>ई-पाठशाला**

ई-पाठशाला मानव संसाधन विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी का संयुक्त उपक्रम है। इसका उद्देश्य पाठ्यपुस्तकों, पत्रिकाओं, दृश्य-श्रव्य संसाधनों व सभी शैक्षिक ई-संसाधनों का प्रसार करना है। इसे नवम्बर 2015 में प्रारम्भ किया गया था। इसमें कक्षा 1-12 तक की समस्त एनसीईआरटी की पुस्तकों को निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। यह पोर्टल शिक्षकों, विद्यार्थियों व अभिभावकों को आईसीटी कार्यक्रम, ई-बुक, व अन्य डिजिटल संसाधन सरलतापूर्वक उपलब्ध कराकर ग्रामीण भारत की डिजिटल खाई पाटने के लिए तैयार की गई है। इस ऐप को कानून एवं न्याय मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी विभाग द्वारा डिजिटल इण्डिया अवार्ड- 2019 से भी सम्मानित किया जा चुका

है।

#### <sup>14</sup> ई-पीजी पाठशाला

भारत सरकार के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने परास्नातक के विद्यार्थियों के लिए ई-पीजी पाठशाला का शुभारम्भ किया जिसका संचालन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ;न्वद्ध करता है। ई-पीजी पाठशाला पर उपलब्ध सामग्री देश के अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार की गई है। इसमें उपलब्ध सामग्री परास्नातक के पाठ्यक्रम के अनुसार ही है। इसमें लगभग 70 विषयों में उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यक्रम आधारित, संवादात्मक सामग्री उपलब्ध है।

#### <sup>15</sup> शालादर्पण

यह देश के सभी केन्द्रीय विद्यालयों के लिए एक ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों शिक्षकों, अभिभावकों व समुदाय के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार विद्यालय प्रशासन की दक्षता, विद्यालयों का संचालन व अन्य सेवाएं प्रदान करना है।

#### <sup>16</sup> शाला सिद्धि

राष्ट्रीय विद्यालय मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम ;छत्तैन्द्र को 'शालासिद्धि' कहा जाता है। यह कार्यक्रम विद्यालय मूल्यांकन को सुधार के एक साधन के रूप में तथा विद्यालय के उन्नयन को एक लक्ष्य के रूप में देखता है। इसे राष्ट्रीय शैक्षिक योजना व प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया है।

भारत सरकार द्वारा चलाये गए उपरोक्त कार्यक्रम निश्चित रूप से लाभदायक हैं। ऑनलाइन शिक्षण पद्धति को छात्र एक लचीले विकल्प के रूप में देखते हैं। शिक्षकों को भी तकनीकी के सहयोग से अपनी अध्यापन योजना को बेहतर बनाने में सुविधा होती है, साथ ही नवाचार के माध्यम से वे विद्यार्थियों को और अधिक प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित कर पाते हैं। विभिन्न एप्लीकेशन्स जैसे जूम, गूगल मीट, गूगल क्लास, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से जो भी शिक्षा व शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है वह कोविड-19 महामारी के इस कठिन समय में अत्यन्त आवश्यक है। केन्द्र व राज्य सरकारों, शिक्षण संस्थानों, विद्यार्थियों, शिक्षकों व अभिभावकों के शिक्षा हेतु ये संयुक्त प्रयास अत्यन्त सराहनीय हैं।

#### कोविड-19 का शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव

कोविड-19 महामारी ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं। इसने हमारी परम्परागत शिक्षण पद्धति को ही बदल कर रख दिया है। प्राथमिक हो या माध्यमिक या उच्च शिक्षा, प्रत्येक स्तर पर विद्यार्थियों का पठन-पाठन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। भारत जैसे देश में अभी ऑनलाइन शिक्षण और मूल्यांकन पर पूर्ण निर्भरता संभव नहीं है परन्तु कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों ने शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन शिक्षण हेतु विवश कर दिया। शिक्षकों, अभिभावकों व विद्यार्थियों के सामने इस नई शिक्षण पद्धति के साथ सामन्जस्य बिठाना बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, तकनीकी ज्ञान आदि से सम्बन्धित अनेक समस्याएं हैं। यहाँ हम कुछ प्रमुख समस्याओं की बात करेंगे जो इस महामारी के कारण उत्पन्न हुई हैं-

#### डिजिटल साक्षरता और तकनीकी सुविधाओं का अभाव

कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु अनेक महत्वपूर्ण प्रयत्न किये। शिक्षण कार्य ऑनलाइन माध्यम से किया जाने लगा परन्तु अधिकांश शिक्षकों, छात्रों व अभिभावकों को तकनीकी की अधिक जानकारी नहीं है। वे कम्प्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल आदि की सहायता से पढ़ने-पढ़ाने हेतु प्रशिक्षित नहीं हैं। इसके साथ ही सभी के पास कम्प्यूटर/टैबलेट/लैपटॉप/मोबाइल आदि उपलब्ध भी नहीं हैं।<sup>17</sup> राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन ;छैव्द की वर्ष 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार केवल 42 प्रतिशत शहरी और 15 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास इन्टरनेट की सुविधा है। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा डिजिटल शिक्षा पर निर्भरता उचित नहीं है।<sup>18</sup> अगस्त 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के आर्थिक परिणामों के फलस्वरूप अगले वर्ष (2021-22) में लगभग 24 मिलियन बच्चों पर स्कूल न लौट पाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में कहा गया है विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों के बन्द होने से विश्व की लगभग 94 प्रतिशत विद्यार्थियों की आबादी प्रभावित हुई है। निम्न व निम्न मध्यम आय वाले देशों में यह संख्या 99 प्रतिशत है। इस महामारी ने शिक्षा प्रणाली में मौजूद असमानता को और अधिक बढ़ा दिया है। डिजिटल शिक्षा के प्रचलन में महिला वर्ग भी काफी संवेदनशील है क्योंकि इनके पास डिजिटल संसाधन काफी कम हैं। इसके कारण बालिकाओं का अपव्यय व अवरोधन तथा बाल विवाह, लिंग आधारित हिंसा आदि की समस्याएँ अधिक देखने को मिल सकती हैं।

#### तकनीकी रूप से अप्रशिक्षित

ऑनलाइन शिक्षा के मार्ग में आने वाली चुनौतियों में यह भी एक बड़ी समस्या है कि अधिकांश शिक्षक

**शिक्षक, विद्यार्थी व अभिभावक**

इसके लिए प्रशिक्षित नहीं हैं। अधिकांश शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें तकनीकी के बारे में बुनियादी ज्ञान का भी अभाव है। यद्यपि ई-शिक्षा भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में पहले से ही मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (Moocs) प्लेटफार्म पर 'स्वयं'(Swayam) के रूप में आ चुकी थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन मुफ्त ई-लर्निंग प्लेटफार्म है जिसका उद्देश्य असीमित भागीदारी और वेब के माध्यम से स्कूल, व्यावसायिक, स्नातक, स्नातकोत्तर व इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों तक खुली पहुँच उपलब्ध कराना है। कोविड-19 महामारी से पूर्व शिक्षा के ऑनलाइन माध्यम को तेजी से अपनाया नहीं गया। परन्तु इस महामारी ने शिक्षण संस्थानों और शिक्षकों को तकनीकी का प्रयोग करने के लिए बाध्य कर दिया। संभावना यह है कि तकनीकी के जानकार केवल युवा शिक्षक ही ऑनलाइन शिक्षण के साथ सामंजस्य बिठाने की क्षमता रखते हैं। वरिष्ठ शिक्षकों में प्रौद्योगिकी को लेकर एक स्वाभाविक विरोध है। शिक्षकों के एक वर्ग में यह भय भी है कि नयी शिक्षा व्यवस्था के मुख्य चरण में एक शिक्षक के तौर पर उनकी भूमिका कम हो जाएगी और शिक्षक का स्थान प्रौद्योगिकी ले लेगी।

ऑनलाइन शिक्षण में शिक्षक और विद्यार्थी के साथ ही अभिभावक की भूमिका भी अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गई है। बिना किसी पूर्व योजना के शिक्षण संस्थानों द्वारा ऑनलाइन शिक्षण प्रारम्भ करवाना अभिभावकों के लिए भी एक बड़ी समस्या है। अधिकांश अभिभावक व छात्रतकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण ऑनलाइन शिक्षण के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। कहीं नेटवर्क की समस्या तो कहीं बच्चों को अनुशासित बनाए रखने में अभिभावक चिंतित है। विद्यालय का कार्य व गृहकार्य दोनों ही करवाने की जिम्मेदारी अब अभिभावकों पर है जिनके कारण वे अपने अन्य कार्यों के निर्वहन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं तथा तनाव में रहने लगे हैं।

**विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव**

कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक गतिविधियाँ रूक जाने से बच्चों की जीवन शैली अत्यन्त प्रभावित हो रही थी। जब ऑनलाइन शिक्षण प्रारम्भ हुआ तो लगा कि सम्भवतः शिक्षण प्रक्रिया अब पटरी पर आ जाएगी। स्कूल प्रबन्धन ने एक रूटीन के तहत बच्चों को घर में ही पढ़ाना प्रारम्भ किया। विद्यालय के यूनीफार्म में बच्चे 5-6 घण्टे कम्प्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के सामने बैठ कर पढ़ाई करने लगे। कुछ समय बीतते ही यह अनुभव होने लगा कि शिक्षण का यह माध्यम बच्चों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इस नवीन शिक्षण पद्धति में सबसे बड़ा खतरा बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ना है। इससे बच्चों के सर में दर्द, आँखों में दर्द, नींद न आना, एकाग्रता में कमी, उदासीनता जैसी समस्याएँ उत्पन्न होने लगी।<sup>19</sup> "अमेरिकन अकादमी ऑफ पीडियोट्रिक्स" ने बच्चों के स्क्रीन टाइम पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार 2 से 5 वर्ष के बच्चे एक घण्टे से अधिक स्क्रीन का उपयोग न करें तथा उन्हें खेलने व अन्य गतिविधियों के समय दें।

**इंटरनेट का गलत उपयोग**

इंटरनेट सूचना का विशाल श्रोत माना जाता है। ऑनलाइन शिक्षा ने इसकी उपयोगिता को और अधिक बढ़ा दिया है परन्तु इसके साथ ही विद्यार्थियों द्वारा इसका दुरुपयोग भी किया जाने लगा है। यह मनोरंजन के प्रचुर श्रोत उपलब्ध कराता है। विद्यार्थी इस पर विभिन्न प्रकार के वीडियो देखते हैं, गेम खेलते हैं और कभी-कभी ऐसी साइटों पर जाते हैं जो कि बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। हिंसा, अश्लीलता व नशा परोसती ये अनपेक्षित साइट्स अल्प आयु वर्ग के बच्चों के बौद्धिक विकास को बाधित करती हैं। कई बार बच्चे अनजाने में ही इंटरनेट पर बहुत सारी व्यक्तिगत जानकारी भी दे देते हैं जिसका संगठन 'क्रोई' (Child Rights and you) 'Online Salty and Internet Addiction' विषय पर दिल्ली एनसीआर के 630 किशोरों पर किये गए अपने अध्ययन में पाया कि इनमें से 92 प्रतिशत बच्चे साइबरहिंसा का शिकार हुए हैं। 13 से 18 आयु वर्ग के जो बच्चे प्रतिदिन 3 घण्टे से अधिक साइबरहिंसा का शिकार हुए जो बच्चे प्रतिदिन 4 घण्टे से अधिक समय इंटरनेट पर व्यतीत करते थे उनमें से 28 प्रतिशत बच्चे साइबर हिंसा के शिकार हुए।

इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया के अत्यधिक प्रयोग ने भी बच्चों का ध्यान अध्ययन से भटकाया है। यह स्थिति अब और भी गंभीर हो गई है। क्योंकि अभिभावक अब बच्चों को मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप आदि देने के लिए बाध्य है ताकि उनकी ऑनलाइन शिक्षा में कोई बाधा न आए। इंटरनेट के इन दुष्प्रभावों ने अभिभावकों को चिंता में डाल दिया है। अब उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि

उनके बच्चे इंटरनेट का सकारात्मक उपयोग ही करें।

### कोविड-19 का शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव

कोई भी परिवर्तन चाहे वह कितना भी विघटनकारी हो अपने साथ कुछ न कुछ सम्भावनाएं अवश्य लेकर आता है। कोविड-19 महामारी भी ऐसी ही आपदा है जिसने हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था आदि के सम्मुख गम्भीर संकट उत्पन्न कर दिये परन्तु इससे हमारी शिक्षा व्यवस्था में कुछ ऐसे परिवर्तन भी आए जो अत्यधिक सकारात्मक रहे। समाज में तीव्र गति से हो रहे परिवर्तनों के साथ ही शिक्षण की परम्परागत पद्धति में भी बदलावों की आवश्यकता थी जो कि इस महामारी के कारण सम्भव हो सके। विभिन्न नवाचारों के साथ हमने शिक्षा के डिजिटल स्वरूप को स्वीकारा जिससे कोविड-19 के इस कठिन दौर में भी शिक्षण प्रक्रिया लम्बे समय तक स्थगित नहीं रही। इस महामारी के शिक्षा पर सकारात्मक प्रभावों को निम्न बिन्दुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है-

### मिश्रित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा

मिश्रित शिक्षा प्रणाली एक औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम है जिसमें विद्यार्थी पाठ्यक्रम का कुछ भाग कक्षा में और कुछ भाग डिजिटल और ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से पूर्ण करता है। इसे प्रौद्योगिक समर्थित शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है। इस शिक्षा में समय स्थान विधि आदि का नियंत्रण विद्यार्थी के हाथ में होता है। भारत में ऑनलाइन शिक्षण का प्रचलन नया नहीं है। कई सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन कक्षाएं काफी पहले से चल रही हैं। कोविड-19 के कारण इसमें काफी तेजी आई है। तेजी से परिवर्तित होती प्रौद्योगिकी ने ही ज्ञान अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। जिसमें शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण है। भविष्य में पारम्परिक तरीकों से शिक्षण के साथ ही नवीन तकनीक को भी सम्मिलित करना आवश्यक है। यद्यपि कोविड-19 के इस दौर में इसका प्रचलन प्रारम्भ हो चुका है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई है। इसमें समय और संसाधन कम लग रहे हैं। इसकी कुछ सीमाओं के बावजूद बड़ी संख्या में शिक्षकों और विद्यार्थियों ने इसे अपनाने में उत्साह दिखाया है।

### तकनीकी जागरूकता में वृद्धि

भारत में कक्षा शिक्षण का प्रचलन अत्यधिक प्राचीन है। हमारे शिक्षक इसी शिक्षण विधि से पढ़ाने के अभ्यस्त रहे हैं जिसके कारण ऑनलाइन पाठ्यक्रम को अपनाने की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। उच्च शिक्षण संस्थानों हेतु न्चब् ने 2018 की गाइडलाइन्स में ही ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराने की बात की थी परन्तु जनवरी 2020 तक देश के केवल सात उच्च शिक्षण संस्थान ही ऐसे थे जिन्होंने न्चब् के इन निर्देशों का पालन किया। कोविड-19 के दौरान लगे लॉकडाउन में जब शिक्षण संस्थान बन्द हो गये तो न्चब् ने सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी तकनीकी पर आधारित संसाधनों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में पहल की एक सूची जारी की। इसके माध्यम से विद्यार्थी स्वयं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी आदि विकल्पों के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इसके साथ ही व्हाट्सएप, गूगल मीट, जूम, यूट्यूब, गूगल क्लासरूम आदि के माध्यम से भी शिक्षण कार्य होने लगे। जिन शिक्षकों, विद्यार्थियों व अभिभावकों को इन तकनीकों की जानकारी नहीं थी, उनहोंने भी धीरे-धीरे इसे सीख लिया और अब वे इस नवीन शिक्षण पद्धति के साथ सहज हो गये।

### मुक्त और दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा

दूरस्थ शिक्षा प्रणाली वह है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी को किसी समय विशेष या स्थान विशेष पर उपलब्ध होने की आवश्यकता नहीं होती। भारत में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में राज्यों के मुक्त विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थाएं तथा विश्वविद्यालय सम्मिलित है। इसमें विद्यार्थी को नियमित रूप से किसी संस्थान जाकर अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होती। सभी पाठ्यक्रमों के लिए कक्षाओं की संख्या तय होती है और इंटरनेट के उपयोग के कारण विद्यार्थी देश में कहीं भी रहकर घर से अध्ययन कर सकता है। कोविड-19 महामारी के इस दौर में शिक्षा का यह माध्यम अत्यन्त उपयोगी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में भी मुक्त और दूरस्थ शिक्षा की प्रासंगिकताको स्पष्ट रूप से स्वीकारा गया है। इसके बिन्दु 10.10 में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा से सकल नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त करने और शाश्वत विकास के लक्ष्य-2030 को सफलतापूर्वक अर्जित करने में भी योगदान की अपेक्षा की गई है। साथ ही ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को परम्परागत पाठ्यक्रमों के साथ मिश्रित रूप से बढ़ावा देने की चर्चा की गई है। कोविड-19 महामारी ने वर्तमान सत्र में परम्परागत शिक्षा व्यवस्था के सम्मुख जो चुनौती खड़ी की है उसका समाधान ऑनलाइन शिक्षण व मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से काफी सीमा तक किया जा सकता है।

**सहयोगात्मक कार्यों को बढ़ावा**

कोविड-19 ने शिक्षकों और विद्यार्थियों में सहयोग व एक टीम के रूप में कार्य करने की भावना को जन्म दिया। शिक्षक अपने विचारों, संसाधनों और शिक्षण-विधियों को लेकर अपने साथी शिक्षकों के साथ अन्तर्क्रिया करने लगे। नवीन तकनीकों को सीखने-सिखाने में एक दूसरे का सहयोग करने लगे। 21<sup>व</sup> शताब्दी के जम्बीपदह ंदक संतदपदह प्दजमतदंजपवदंस ैनतअमलसे प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार 61 प्रतिशत शिक्षकों ने माना कि वे महीने में कम से कम एक बार विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान के विकास हेतु अपने सहयोगी शिक्षकों के साथ चर्चा करते हैं। लगभग 47 प्रतिशत शिक्षक ने कहा कि वे महीने में कम से कम एक बार अपने शिक्षकों साथियों के साथ शिक्षण सामग्री का आदान-प्रदान करते हैं। इस प्रकार से इस महामारी ने आपसी सहयोग और साथ-साथ कार्य करनेकी भावना का विकास किया।

उपरोक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट होता है कि इस महामारी से विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक क्षति अवश्य हुई है परन्तु इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं जिससे भविष्य में इस प्रकार की चुनौतियों से निपटने में हम सक्षम होंगे।

**निष्कर्ष**

प्रस्तुत शोधपत्र में कोविड-19 महामारी का शिक्षा के क्षेत्र में प्रभाव तथा सरकार द्वारा शैक्षिक उन्नयन हेतु किये गये प्रयासों की विवेचना की गई है। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार सरकार द्वारा इस महामारी से शिक्षा के क्षेत्र को प्रभावित होने से बचाने के लिए अनेक प्रयास किये गये। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए डिजिटल/ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दिया गया। शिक्षा का यह नवीन स्वरूप भविष्य में शिक्षा को कम लागत वाला व समावेशी बनाएगा। यद्यपि अभी इसमें कुछ कमियाँ हैं। अभी यह शिक्षा प्रणाली सर्वसुलभ नहीं है इसके लिए सरकार सहित सभी हितधारकों को इस ओर मिलकर प्रयास करने चाहिए ताकि आने वाले समय में बड़ी संख्या में छात्रों के लिए ई-लर्निंग से शिक्षा को और अधिक सुलभ बनाया जा सके। इसके लिए डिजिटल शिक्षा से जुड़ी आधारभूत संरचना का विकास सबसे पहले किया जाना चाहिए (विशेषकर ग्रामीण, दुर्गम, पहाड़ी व सीमावर्ती क्षेत्रों में)। छात्र-छात्राओं के साथ-साथ शिक्षकों में भी डिजिटल साक्षरता का प्रचार-प्रसार करना चाहिए। इसके साथ ही सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर की उपलब्धता पर भी ध्यान देना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र के अग्रणी गैर सरकारी संगठनों को साथ लेकर सभी भारतीयों तक इस नवीन शिक्षण पद्धति की उपलब्धता व जानकारी सुनिश्चित कराई जानी चाहिए। इन प्रयासों से सभी के लिए डिजिटल शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है साथ ही कोविड-19 जैसी किसी भी चुनौती के लिए भविष्य में तैयार रखा जा सकता है। यहाँ पर यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि हमें अपनी परम्परागत शिक्षण पद्धति (कक्षा शिक्षण) को हतोत्साहित नहीं करना है बल्कि मिश्रित शिक्षण को बढ़ावा देकर दोनों का ही लाभ उठाना है। कक्षा-कक्षों में शिक्षण के जो लाभ हैं, हो सकता है कि वे ऑनलाइन शिक्षण में न मिल सकें। परम्परागत शिक्षण में शिक्षक और विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर एक दूसरे से अन्तर्क्रिया करते हैं। कक्षा में बच्चों को संस्कार और जीवन मूल्य सिखाये जाते हैं, साथ ही शिक्षक का एक नैतिक अनुशासन होता है वहीं ऑनलाइन शिक्षण में अनुशासन की कमी होती है, वार्तालाप की संभावनाएं बहुत सीमित होती हैं, वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में हम घर बैठे कम समय में एक साथ कई विषयों का ज्ञान ले सकते हैं, कभी भी कहीं से भी उपयोगी शिक्षण सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, जबकि कक्षा-शिक्षण में यह सम्भव नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार की शिक्षण व्यवस्था हमारे लिए आवश्यक है। अतः मिश्रित शिक्षण व्यवस्था को प्रोत्साहन देकर हमें अपनी परम्परागत शिक्षण व्यवस्था के साथ ही भविष्य के लिए उपयोगी डिजिटल शिक्षा को भी अपनाना होगा।

प्रत्येक त्रासदी, प्रत्येक आपदा हमें कुछ न कुछ सिखाती है। यह आपदा भी हमें सीख देती है कि हमें अपने देश का विकास अपनी परिस्थितियों, अपने लोगों की आवश्यकताओं और देशज विचारों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। यह महामारी हमें सीख देती है कि हमारी शिक्षा प्रणाली हमारे समाज और समुदाय की आवश्यकताओं तथा हमारे संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप होने चाहिए न कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा हेतु। तभी हमारा देश कोविड-19 जैसी महामारी की चुनौतियों का सामना करते हुए 'सभी के लिए शिक्षा के अपने लक्ष्य' को प्राप्त कर पाएगा।

**सन्दर्भ ग्रन्थ सूची**

1. Raj, Utsav, "Indian Education System in Fight Against Covid-19 Pandemic" *IJCRT V.8, Issue 7, July 2020, P.P. 2086-87.*



2. लेंका रवीन्द्रनाथ व अवनीश त्रिपाठी, “ग्रामीण भारत में डिजिटल शिक्षा और वर्चुअल लर्निंग” कुरुक्षेत्र, दिसम्बर 2020
3. “भारत में ऑनलाइन शिक्षा 2021” केपीएमजी और गूगल रिपोर्ट 2017।
4. शेट्टी, निखिल “कोविड-19 के बाद भारत का भविष्य: शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन” शिक्षा संशोधन वा-3 अंक 3 मई-जून 2020. चर्चा 87.88
5. Dawan Shivangi, "Online Learning: A Panacea in the Time of Covid-19 Crisis", *Journal of education Technology system*, v.49(1) June 2020, P.P. 10-12
6. Raj Utsav, "Indian Education system in Fight Against Covid-19 Pandemic". *IJCRT* v.8, Issue 7 July 2020. P.P. 20890-91
7. <https://diksha.gov.in>
8. <https://nishtha.ncert.gov.in>
9. <https://swayamprabha.gov.in>
10. <https://swayam.gov.in>
11. <https://nroer.gov.in>
12. <https://ndl.gov.in>
13. <https://epathshala.nic.in>
14. <https://epgp.inflibnet.ac.in>
15. <https://darpan.kvs.gov.in>
16. <https://shaalasiddhi.niepa.ac.in>
17. NSO Report on education (2017-18)
18. मधुसूदन, गजेन्द्र सिंह, “पारम्परिक अर्थव्यवस्था से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर” कुरुक्षेत्र, नवम्बर 2020.
19. "More screen Time During Pandemic can lead to eye strain". Report of AAP, Dec 2020.
20. "Online safety and Internet Addiction". Report of CRY Feb 2020.
21. <https://oecd.org>